



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 अगस्त, 2004/11 भावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 22 जुलाई, 2004

संख्या बी०एल० पी०-पंच-37615-73.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी अण्डुता द्वारा छानबीन उपरान्त श्री मुंशी राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड अण्डुता, जिला बिलासपुर के दिनांक 8-4-2004 को चौथी संतान (लड़की) पैदा हुई है जिस पर उक्त पंचायत गदाधिकारी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) व 2 (11) तथा 131 (2) जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2000 (संशोधित) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था कि क्यों न इस तथ्य पर उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए। इस बारे में उन्हें दिनांक 13-7-2004 को सायं 3 बजे अपना पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताधरी के सम्मुख सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा उन्होंने व्यक्तिगत तौर से लिखित व्यान दिया है कि "मेरे दिनांक 8-4-2004 को चौथी संतान लड़की पैदा हुई है तथा इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। जिससे उक्त उप-प्रधान के पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (0) व 2 (11) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131 (2) के अन्तर्गत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार के पद को रिक्त घोषित करता हूँ तथा उन्हें आदेश देता हूँ कि यदि उक्त

उप-प्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धन राशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कुलजयार को सौंप दें।

बिलासपुर, 22 जुलाई, 2004

संख्या जी० एल० पी०-पंच-3774-81. — क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, झण्डुता द्वारा छानबीन उपरान्त श्री छोटु राम, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलजयार, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के परिवार रजिस्टर भाग-1 की प्रमाणित प्रति अनुसार तीन संतानें हैं जिसमें अंतिम संतान लड़की दिनांक 2-11-2001 को पैदा हुई है। जिस पर उक्त पंचायत पदाधिकारी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) व 2 (11) तथा 131 (2) जो हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 2000 (संशोधन) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था कि क्यों न इस तथ्य पर उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए। इस बार उन्हें दिनांक 13-7-2004 को सायं 3 बजे अपना पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। परन्तु वे न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित उत्तर दिया है लेकिन नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने पावती इस कार्यालय को भेजी है जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। जिससे उक्त सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (0) व 2 (11) के अन्तर्गत श्री छोटु राम को सदस्य पद से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131 (2) के अन्तर्गत सदस्य, ग्राम पंचायत कुलजयार के पद को रिक्त घोषित करता हूँ तथा उन्हें आदेश देता हूँ कि यदि उक्त सदस्य के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धन राशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कुलजयार को सौंप दें।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

चम्बा, 26 जुलाई, 2004

क्रमांक चम्बा-पंच-1 (50)/2000-742-50. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, राहुल आनन्द (भा० प्र० से०), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति तीसा के निर्वाचित अध्यक्ष के नाम का सर्वसाधारण जनता की सूचना हेतु प्रकाशन करता हूँ :—

सारणी

क्र० सं०	पंचायत समिति	पद नाम	निर्वाचित अध्यक्ष का नाम व पता
1.	तीसा	अध्यक्ष	श्री होशियार सिंह सुपुत्र श्री अमर नाथ, निवासी गांव व डा० वैरागढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा।

राहुल आनन्द
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी 26 जुलाई, 2004

संख्या पी0सी0एन0-एम0-एन0डी0/2001-2745-48. — यतः श्री जीवन लाल, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदर मण्डी (वार्ड नं० 3 भरगांव) द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 104/2, रकबा तादादी 4-1-11 बीघा तथा 138/5 रकबा तादादी-0-2-18 बीघा पर अवैध कब्जा करने वाले विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), सदर मण्डी से उनके पत्र संख्या एस0डी0एम0/एम0एन0डी0/एम0सी0/2003-3691, दिनांक 3-12-2003 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त सदस्य द्वारा अभी भी सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार "ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी को या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिग्रहण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको वे देखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकांता न रहा हो"।

अतः मैं, श्री राजा रिजवी, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) एतद्वारा श्री जीवन लाल सुपुत्र श्री लक्ष्मण दास, गांव वडा० भरगांव, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी (पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदर, मण्डी) (हि० प्र०) को आदेश देता हूँ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है, और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व 122 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें पंचायत समिति की सदस्यता से निर्हित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

मण्डी, 26 जुलाई, 2004

संख्या पी0सी0एन0-एम0एन0डी0/2001-2741-44. — यतः श्री कंवर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डी सपनोट, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि० प्र०) द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 1767/1581/1, रकबा तादादी 13-6-10 बीघा पर अवैध कब्जा करने वाले विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), करसोग, जिला मण्डी से उनके पत्र संख्या 2 के0एस0जी0/एम0डी0/2003-3270, दिनांक 7-11-2003 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त उप-प्रधान द्वारा अभी भी उक्त सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार "ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी को या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिग्रहण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे वे देखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकांता न रहा हो"।

अतः मैं, श्री राजा रिजवी (भा० प्र० से०), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) एतद्वारा श्री कंवर लाल उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डी-सपनोट, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि० प्र०) को आदेश देता हूँ कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित

रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है, और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व 122 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें उप-प्रधान के पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

मण्डी, 26 जुलाई, 2004

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-2761-64.—यतः श्री बेली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 995/1, रकबा तादादी 3-17-0 बीघा पर अवैध कब्जा करने वाले विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), सदर, जिला मण्डी से उनके पत्र संख्या एस० डी० एम०/ओ० के०/2004-1926, दिनांक 19-5-2004 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त प्रधान द्वारा अभी भी उक्त सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है;

और यह कि हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के प्रावधान अनुसार “ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हरित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रांता न रहा हो”।

तयः मैं, श्री रजा रिजवी (भा० प्र० से०), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद् द्वारा श्री बेली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०) को आदेश देता हूँ कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है, और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व 122(2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें प्रधान पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

मण्डी, 26 जुलाई, 2004

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-2749-52.—यतः श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भांम्बला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 183/1, रकबा तादादी 0-00-20 है० पर अवैध कब्जा करने वाले विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), सरकारघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश से उनके पत्र संख्या 4117, दिनांक 2-12-2003 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त प्रधान द्वारा अभी भी उक्त सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा है;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के प्रावधान अनुसार “ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हरित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रांता न रहा हो”।

तयः मैं, श्री रजा रिजवी, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद् द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भांम्बला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूँ कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित

रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है, और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व 122(2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें प्रधान पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

मण्डी, 26 जुलाई, 2004

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-2753-56.—यतः श्री रतन चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत तलकेहड़, विकास खण्ड चौन्तड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 783/210/1, रकबा तादादी 0-1-16 बीघा पर अवैध कब्जा करने बारे विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश से उनके पत्र संख्या का० अ०/2004-2392, दिनांक 2-6-2004 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त प्रधान का अभी भी उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा है ;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार "ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हरित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाईटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।"

अतः मैं, अली रजा रिजवी, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद् द्वारा श्री रतन चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत तलकेहड़, विकास खण्ड चौन्तड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूँ कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व 122 (2) के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें प्रधान पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

मण्डी, 26 जुलाई, 2004

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-2757-60.—यतः श्री लेद राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कल्हणी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं० 503/425/1 व 503/425/2, कित्ता 2 रकबा तादादी 7-14-17 बीघा पर अवैध कब्जा करने बारे विस्तृत रिपोर्ट उप-मण्डल अधिकारी (ना०), गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट में पाया गया कि उपरोक्त प्रधान का अभी भी उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है ;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार "ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्हरित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाईटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिसूचित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।"

अतः मैं, अली रजा रिजवी, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद् द्वारा श्री लेद राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कल्हणी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूँ कि वह

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अधीहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी न कहना है, और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व 122 (2) के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही क्रम में लाते हुए प्रधान पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 22 जुलाई, 2004

संख्या पी०सी०एन०-एस०एम-आर० (5) 50/96-III-4157-66.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर द्वारा ग्राम पंचायत घोंडा के प्रधान श्री नागेन्द्र सिंह का त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है। इस पदाधिकारी द्वारा त्याग-पत्र उसकी शिक्षा विभाग में नियुक्ति हो जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, एम० एस० नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम-135 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नागेन्द्र सिंह का त्याग-पत्र दिनांक 11-6-2004 से स्वीकार करता हूँ। अतः श्री नागेन्द्र सिंह को आदेश दिये जाते हैं कि यदि उसके पास उक्त ग्राम पंचायत का कोई भी रिकार्ड, सामान, राशि या अन्य सम्पत्ति हो तो वह उसे तुरन्त ग्राम पंचायत को सौंपना सुनिश्चित करें।

एम० एस० नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश।